PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 148
दि. 27.09.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

शांतिपूर्ण आवाज उठाना नागरिकों का अधिकार, न्यायपालिका करेगी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा : सीजेआई सूर्यकांत

पटना में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों से सीजेआई का खुला संवाद, कॉलेजियम, कानूनी शिक्षा, फीस और युवा वकीलों की चुनौतियों पर भी हुई चर्चा

पटना। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा है कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का पूरा संवैधानिक अधिकार है और न्यायपालिका ऐसे अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि असहमति लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है और जब कोई नागरिक या छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है तो उसके अधिकारों की संवैधानिक कसौटी पर रक्षा की जानी चाहिए। सीजेआई शनिवार को चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (सीएनएलयू), पटना में आयोजित छात्रों के साथ खुले संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली से लेकर कानून की पढ़ाई, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कॉलेजियम व्यवस्था और युवा वकीलों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों तक कई महत्वपूर्ण सवाल सीधे मुख्य न्यायाधीश के सामने रखे। कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। छात्र ने सवाल किया कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल का इस्तेमाल करती है तो ऐसे मामलों में न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि संविधान नागरिकों को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने और अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आवाज को महत्व दिया जाता है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना नागरिक अधिकारों का हिस्सा है। यदि किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से बल प्रयोग किए जाने की शिकायत सामने आती है, तो अदालतें उपलब्ध तथ्यों और कानून के आधार पर ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करती हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है और किसी भी मामले में कानून के अनुरूप ही निर्णय लिया जाता है। छात्रों के साथ संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी कॉलेजियम व्यवस्था रहा। विद्यार्थियों ने सीजेआई से पूछा कि कॉलेजियम में किसी उम्मीदवार के संबंध में व्यक्त की गई असहमति या नकारात्मक टिप्पणियों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। इस सवाल पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक

नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी उम्मीदवार के बारे में की गई प्रतिकूल टिप्पणियां उसकी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में इस तरह की संवेदनशील सूचनाओं को सार्वजनिक करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी होता है। उन्होंने संकेत दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा और न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा जैसे पहलुओं का भी ध्यान रखा जाता है। कानूनी शिक्षा की बढ़ती लागत का मुद्दा भी छात्रों ने प्रमुखता से उठाया। विद्यार्थियों ने कहा कि देश में अच्छे विधि संस्थानों में पढ़ाई की फीस लगातार बढ़ रही है, जबकि छात्रवृत्ति के अवसर सीमित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए महंगी कानूनी शिक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। छात्रों ने यह भी सवाल उठाया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा वकीलों को शुरुआती वर्षों में आर्थिक स्थिरता हासिल करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीजेआई सूर्यकांत ने युवा वकीलों की इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि वकालत के शुरुआती वर्षों में संघर्ष सामान्य बात है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे धैर्य बनाए रखें, लगातार अध्ययन करते रहें और अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्धता कायम रखें। उन्होंने कहा कि कानून का पेशा केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निरंतर अध्ययन, अनुभव और व्यावहारिक समझ की जरूरत होती है। एक अच्छे वकील के लिए कानून की किताबों के साथ-साथ न्यायालय की कार्यप्रणाली और समाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है। उनके मुताबिक शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद यदि युवा वकील अपने ज्ञान और पेशेवर कौशल को लगातार विकसित करते रहें तो वे आगे चलकर न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम में विधि शिक्षा के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। सीएनएलयू के कुलपति प्रो. फैजान मुस्तफा ने पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण को और मजबूत करने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पांच वर्षीय कानून पाठ्यक्रम में चार वर्षों की शैक्षणिक पढ़ाई के बाद अंतिम वर्ष में अनिवार्य कोर्ट अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका कहना था कि इससे विद्यार्थियों को अदालतों की वास्तविक कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने और कानून के व्यावहारिक पक्ष का अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा। प्रो. मुस्तफा के इस सुझाव को सीजेआई सूर्यकांत ने सकारात्मक रूप से लिया। उन्होंने माना कि कानून की शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण का महत्व भी बेहद अधिक है। अदालत में होने वाली कार्यवाही, दलील रखने की प्रक्रिया, दस्तावेजों की तैयारी, न्यायिक अनुशासन और मुकदमों की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का अवसर विद्यार्थियों को उनके पेशेवर जीवन के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकता है। कोर्ट अप्रेंटिसशिप जैसे प्रस्तावों से कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही न्यायिक वातावरण की समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है। खुले संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने न्यायपालिका की भूमिका और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई अन्य सवाल भी सामने रखे। सीजेआई ने छात्रों की जिज्ञासाओं का जवाब देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम न्यायपालिका और युवा पीढ़ी के बीच संवाद को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि कानून के विद्यार्थी भविष्य में वकील, न्यायाधीश, शिक्षक और कानून से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसलिए उनके लिए न्यायिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझना और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सजग रहना आवश्यक है। सीजेआई सूर्यकांत ने संवाद के दौरान छात्रों के सीधे और बेबाक सवालों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें युवाओं के साथ इस तरह के खुले सवाल-जवाब पसंद हैं, क्योंकि इससे उन्हें विद्यार्थियों की सोच, उनकी जिज्ञासाओं और कानून के क्षेत्र से जुड़ी वास्तविक चिंताओं को समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने छात्रों को सवाल पूछने, अध्ययन करने और अपने विचारों को तार्किक तरीके से रखने के लिए प्रोत्साहित किया। पटना में आयोजित यह संवाद कार्यक्रम केवल न्यायपालिका और कानून की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, न्यायिक नियुक्तियों, विधि शिक्षा और पेशेवर जीवन से जुड़े व्यापक विषयों पर चर्चा हुई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार से लेकर कॉलेजियम व्यवस्था में गोपनीयता और कानून की पढ़ाई में व्यावहारिक प्रशिक्षण तक छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों ने यह भी दिखाया कि युवा पीढ़ी न्याय व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को लेकर गंभीरता से सोच रही है। सीजेआई सूर्यकांत के साथ सीधे संवाद ने विद्यार्थियों को न्यायपालिका के शीर्ष स्तर से अपने सवालों के जवाब पाने का अवसर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य कानून के विद्यार्थियों और न्यायपालिका के बीच संवाद की ऐसी परंपरा को मजबूत करना भी रहा, जिसमें युवा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहें, बल्कि संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और न्यायिक संस्थाओं की भूमिका को व्यापक संदर्भ में समझ सकें।

ड्रम में बंद मिला हिंदू कारोबारी का शव, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर फिर सवाल

ढाका। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक हिंदू आभूषण कारोबारी की संदिग्ध हत्या का मामला सामने आने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंताएं एक बार फिर सामने आई हैं। बेगुनबाड़ी इलाके में बुधवार सुबह एक नहर में तैरते मिले ड्रम के भीतर 50 वर्षीय कारोबारी निरंजन चंद्र सूत्रधार का शव बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार सुबह बेगुनबाड़ी क्षेत्र में स्लूइस गेट के पास नहर में एक ड्रम पानी पर तैरता दिखाई दिया। ड्रम को देखकर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ड्रम को नहर से बाहर निकाला। जब पुलिस ने ड्रम खोला तो उसके अंदर एक व्यक्ति का शव मिला। शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए गए।

पुलिस को मृतक की जेब से मयमनसिंह हिंदू कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन का एक टोकन मिला। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने संबंधित संस्था से संपर्क किया। इसके बाद मृतक की पहचान निरंजन चंद्र सूत्रधार के रूप में हुई। बताया गया कि निरंजन चंद्र अठारबारी क्षेत्र में साझेदारी में आभूषण की दुकान चलाते थे। उनकी पहचान सामने आने के बाद पुलिस ने परिवार को सूचना दी। बाद में उनकी पत्नी सुमिता रानी सूत्रधार और पुत्र जॉय सूत्रधार ने शव की पहचान की।

कोतवाली मॉडल थाना पुलिस के अनुसार, मृतक के सिर और छाती पर धारदार हथियार से किए गए हमले के गंभीर निशान मिले हैं। इन चोटों के आधार पर पुलिस हत्या की आशंका को लेकर जांच आगे बढ़ा रही है। हालांकि घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था और हत्या कब तथा कहां की गई, इसे लेकर अभी जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतक को किस स्थान से ड्रम में बंद कर नहर तक लाया गया और इस पूरी घटना में कितने लोग शामिल थे।

जांच एजेंसियां मृतक की निजी और कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां भी जुटा रही हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या से पहले निरंजन चंद्र किन लोगों के संपर्क में थे और क्या हाल के दिनों में उनका किसी व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था। आभूषण के कारोबार से जुड़े लेन-देन तथा अन्य संभावित कारणों की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित पहलुओं की जांच की जाएगी। घटना के सामने आने के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का कहना है कि निरंजन चंद्र की हत्या ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। उन्होंने पुलिस से घटना की निष्पक्ष जांच करने, हत्या में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिवार यह जानना चाहता है कि कारोबारी की हत्या के पीछे क्या वजह थी और उन्हें किस परिस्थिति में निशाना बनाया गया।

निरंजन चंद्र की हत्या की खबर सामने आने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चल रही बहस भी फिर चर्चा में आ गई है। देश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से चिंता व्यक्त की जाती रही है। हाल के महीनों में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को लेकर भी विभिन्न पक्षों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। ऐसे माहौल में एक हिंदू कारोबारी का शव इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मिलना सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।

हालांकि पुलिस की जांच अभी शुरुआती चरण में है और हत्या के पीछे किसी विशेष कारण या सामुदायिक उद्देश्य की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए घटना के कारण को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा। पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मृतक की हत्या की परिस्थितियों का पता लगाना और इसमें शामिल लोगों की पहचान करना है। इसके लिए घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के साथ-साथ मृतक के संपर्कों, कारोबारी गतिविधियों और हाल के घटनाक्रमों की जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विभिन्न कोणों से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हत्या की प्रकृति और समय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। जांच में यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मयमनसिंह की इस घटना ने एक परिवार से उसका सदस्य छीन लिया है और साथ ही इलाके में भय तथा चिंता का माहौल पैदा किया है। मृतक के परिजन जल्द न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब पुलिस जांच से यह स्पष्ट होना बाकी है कि निरंजन चंद्र सूत्रधार की हत्या किसने, क्यों और किन परिस्थितियों में की तथा हत्या के बाद शव को ड्रम में बंद कर नहर में फेंकने के पीछे क्या मकसद था। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

कांगो में सैन्य विमान दुर्घटना, दो वरिष्ठ जनरलों समेत 14 की मौत,किकविट से राजधानी किंशासा लौट रहा था विमान, केन्गो क्षेत्र में हुआ हादसा ; तकनीकी खराबी की आशंका, दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू

किंशासा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब सैन्य विमान दक्षिण-पश्चिमी शहर किकविट से राजधानी किंशासा की ओर लौट रहा था। उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी समस्या आने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद विमान केन्गो क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। मृतकों में कांगो की सेना के दो वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं। घटना के बाद सैन्य और नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

कांगो सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल एफोमी एकेन्गे ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में सैन्य न्यायालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुटोम्बो कतालयी टिएंडे और सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया की भी मौत हो गई। दोनों अधिकारी कांगो की सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य और विमान के चालक दल से जुड़े लोग भी दुर्घटना में मारे गए। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद कांगो के सैन्य और प्रशासनिक हलकों में शोक का माहौल है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान किकविट से राजधानी किंशासा के लिए रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान विमान में किसी तरह की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। समस्या सामने आने के बाद विमान केन्गो क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा किस समय हुआ और विमान ने दुर्घटना से पहले कोई आपात संकेत भेजा था या नहीं, इस संबंध में विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही सामने आने की उम्मीद है। दुर्घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने घटनास्थल पर जांच और बचाव संबंधी कार्रवाई शुरू की।

स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के बोर्ड अध्यक्ष ट्राइफॉन किन-की मुलुम्बा ने कहा कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का अभी निश्चित रूप से पता नहीं चल पाया है। विशेषज्ञों की टीम हादसे से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। इसमें विमान की तकनीकी स्थिति, उड़ान से पहले की जांच, मौसम संबंधी परिस्थितियां, पायलट और चालक दल से जुड़ी जानकारी तथा विमान के अंतिम क्षणों की गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है।

विमान हादसों में तकनीकी खराबी की आशंका सामने आने के बाद जांच एजेंसियां आम तौर पर विमान के रखरखाव से संबंधित रिकॉर्ड, इंजन और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की स्थिति तथा उड़ान से पहले किए गए निरीक्षण की जानकारी की जांच करती हैं। हालांकि कांगो के अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना की अंतिम वजह की पुष्टि नहीं की है। इसलिए फिलहाल तकनीकी खराबी को केवल प्रारंभिक आशंका के रूप में देखा जा रहा है। आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विमान दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या था।

इस हादसे में दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौत को कांगो के लिए महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मुटोम्बो कतालयी टिएंडे सैन्य न्यायालय के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल थे। दोनों की जिम्मेदारियां सैन्य संस्थान के भीतर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक ही दुर्घटना में दोनों अधिकारियों की मौत से सेना के वरिष्ठ नेतृत्व में बड़ा नुकसान हुआ है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य लंबे समय से सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। विशेष रूप से देश के पूर्वी हिस्से में कई सशस्त्र और विद्रोही गुट सक्रिय हैं। कांगो की सेना इन गुटों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रही है। इनमें एम-23 विद्रोही समूह प्रमुख रूप से शामिल है। यह समूह पूर्वी कांगो के कई हिस्सों में लंबे समय से सक्रिय रहा है और पिछले कुछ वर्षों में उसके खिलाफ कांगो की सेना के साथ संघर्ष बढ़ा है।

एम-23 की गतिविधियों ने कांगो के पूर्वी क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। संघर्ष के कारण कई इलाकों में आम नागरिकों का विस्थापन हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। कांगो सरकार की सेना पर विद्रोही समूहों के खिलाफ अभियान का लगातार दबाव बना हुआ है। ऐसे समय में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की एक साथ मौत सैन्य नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण क्षति है, हालांकि इस विमान दुर्घटना का विद्रोही गतिविधियों से कोई संबंध है या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कांगो में लंबे समय से जारी संघर्ष का असर केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है। पूर्वी हिस्से में अस्थिरता के कारण मानवीय संकट भी गहराता रहा है। कई क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और विद्रोही संगठनों के बीच संघर्ष के चलते आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कांगो की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है। सरकार विद्रोही समूहों के प्रभाव को कम करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सैन्य अभियान चला रही है।

ऐसे समय में सैन्य विमान दुर्घटना ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सैन्य परिवहन और विमान संचालन की तैयारियों पर भी ध्यान खींचा है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि दुर्घटना किसी सुरक्षा कारण से हुई या केवल तकनीकी अथवा अन्य परिचालन संबंधी वजहों से। अधिकारियों की जांच में यदि विमान के मलबे और उड़ान से संबंधित रिकॉर्ड से कोई महत्वपूर्ण सुराग मिलता है तो दुर्घटना की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है।

हादसे के बाद मृतकों के परिवारों तक सूचना पहुंचाने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। सैन्य अधिकारियों और प्रशासन की ओर से मृतकों के योगदान को याद करते हुए शोक व्यक्त किए जाने की उम्मीद है। सेना के लिए यह दुर्घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें ऐसे अधिकारी मारे गए हैं जो सैन्य न्याय और सशस्त्र बलों की निगरानी से संबंधित महत्वपूर्ण पदों पर थे।

जांच अधिकारियों के सामने अब कई सवाल हैं। विमान में तकनीकी खराबी कब शुरू हुई, क्या चालक दल को किसी समस्या का पहले से संकेत मिला था, विमान ने निर्धारित मार्ग से कोई बदलाव किया था या नहीं और दुर्घटना से पहले पायलट ने कोई आपात संदेश भेजा था या नहीं, इन सभी बिंदुओं की जांच की जा सकती है। साथ ही विमान के रखरखाव और उसकी उड़ान क्षमता से जुड़े दस्तावेज भी जांच का हिस्सा होंगे।

कांगो के नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने फिलहाल दुर्घटना के वास्तविक कारण पर अंतिम निष्कर्ष देने से परहेज किया है। विशेषज्ञों की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विमान किस वजह से नियंत्रण से बाहर हुआ और केन्गो क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना के कारणों की सही जानकारी सामने आने के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर भी निर्णय लिया जा सकेगा।

इस सैन्य विमान दुर्घटना ने कांगो को एक साथ कई स्तरों पर प्रभावित किया है। एक ओर देश ने दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों को खोया है, वहीं दूसरी ओर यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब देश पहले से ही विद्रोही गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है।

संपादकीय

ट्रंप-जिनपिंग वार्ता

वैसे तो चमक-दमक और जोरदार मेहमाननवाजी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वॉशिंगटन में हुई मुलाकात प्रथम दृष्टया शानदार नजर आती है। लेकिन हकीकत में इस समिट का कोई ठोस परिणाम नजर नहीं आया। दिल मिलें न मिलें हाथ मिलाने की तर्ज पर एक बात तो स्पष्ट है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कितनी गहराई तक आपस में जुड़ी हुई हैं। उनमें गहरे मतभेद और मुखर प्रतिद्वंद्विता आज भी कायम है। वार्ता का स्पष्ट परिणाम उनके बीच व्यापारिक युद्ध विराम का आगे बढ़ना है। हालांकि, दोनों देशों के व्यापारिक मामलों को लेकर बुनियादी विवाद अभी खत्म नहीं हुए हैं। अमेरिका ने कई तरह के टैरिफ चीन पर थोपे हैं, अमेरिकी सामान का चीन द्वारा खरीदने का विवाद, रेयर-अर्थ सप्लाई और चीन को दी जाने वाली उन्नत तकनीकों पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी हैं। लेकिन दोनों देशों के कारोबारियों के लिये थोड़े समय की राहत को स्थायी समझौता नहीं माना जा सकता। हालांकि इसके बावजूद इस शिखर सम्मेलन के संकेतिक महत्व को स्वीकार करना होगा। जिस तरह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए रेड कॉर्पेट बिछाया गया, राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप जिस तरह परंपरा को नजरअंदाज करके हवाई अड्डे पर शी जिनपिंग का स्वागत करने गए, उससे प्रतिस्पर्धी दौर में चीन के बढ़ते प्रभाव का ही पता चलता है। ट्रंप ने गर्व के साथ व्हाइट हाउस के नये रूप में तैयार परिसर को उन्हें दिखाया और शानदार राजकीय भोज का भी आयोजन किया। हालांकि, ताइवान के मामले में बहुत कुछ दांव पर लगा था। शी ने वाशिंगटन से ताइवान की आजादी का विरोध करने और इस मुद्दे को संवेदनशील ढंग से संभालने का भी आग्रह किया। जिसे चीन वक्त की समझदारी मानता है। हालांकि, अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर एक अस्पष्ट नीति को अपनाए हुए है। एक ओर अमेरिका ताइवान की अपनी रक्षा करने की नीति का समर्थन तो करता है, लेकिन उसकी संप्रभुता को औपचारिक मान्यता भी नहीं देता। सही मायने में इस बहाने शी ने डोनॉल्ड ट्रंप को चीन की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। उन्होंने अमेरिका को संकेत दिया कि चीन ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। वास्तव में चीनी रणनीति का सिद्धांत उस अवधारणा पर केंद्रित है, जो टकराव के खतरे को बताती है। यह खतरा तब पैदा होता है जब कोई स्थापित शक्ति किसी उभरती शक्ति का सामना करती है। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने मौजूदा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच सैन्य बातचीत की अपरिहार्यता को बताया। साथ ही किसी भी तरह के संकट को टालने के लिये मजबूत तंत्र बनाने का भी आह्वान किया। निस्संदेह, इस तरह की पहल करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजिंग और वाशिंगटन के मध्य असहमति केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों तक विस्तृत है। सही मायने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता खोज हेतु जारी तीव्र होड़ ने इस अंतर को दर्शाया है। आज बेहद तेजी से विकसित होती एआई तकनीक को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं पैदा हुई हैं। दुनिया में एआई के शोध-अनुसंधान की गति को धीमा करने की मांग की जा रही है ताकि मानवता के लिये नया संकट पैदा न हो। एक ओर ट्रंप ने एआई को नियमों से बचाने पर जोर दिया है, वहीं दूसरी ओर शी जिनपिंग ने तर्क दिया कि एआई को इंसानी नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। इसकी भूमिका सिर्फ मानव हित में काम करने तक ही सीमित रहनी चाहिए। दो महाशक्तियों में एआई को लेकर भिन्न-भिन्न नजरिये से स्पष्ट होता है कि भविष्य में इस क्षेत्र में सहयोग शायद मुश्किल होगा। दरअसल, दोनों को भय है कि यदि एआई का नियमन किया गया तो एक देश दूसरे से एआई की तरक्की में पीछे रह सकता है। निस्संदेह, इस शिखर सम्मेलन से भले ही कोई बड़ी कामयाबी हासिल न हुई हो, इसके बावजूद इस मुलाकात का अपना एक विशेष महत्व तो है। शिखर सम्मेलन का महत्व इस बात को लेकर भी है कि वॉशिंगटन और बीजिंग अपनी लगातार बातचीत को व्यावहारिक स्थिरता में बदल सकते हैं। निस्संदेह, दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता को टकराव में बदलने से रोका जाना चाहिए।

Delhi में एकजुट दिखने वाले दल UP में आपस में लड़ रहे, INDIA Bloc की यह कैसी एकता है?

"देखा जाये तो राजनीति में असली परीक्षा मंच पर हाथ मिलाने की नहीं, मैदान में सीट बांटने की होती है। और यहीं से कहानी बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों का हिसाब किताब शुरू होते ही सपा और कांग्रेस के बीच पुरानी दोस्ती की परतें खुरचने लगी हैं।

दिल्ली में विपक्षी गठबंधन INDIA के भीतर एक बार फिर एकजुटता की कवायद तेज हो गयी है। चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दे पर साझा लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है, नेताओं के बीच बातचीत बढ़ी है और दिल्ली में सभी विपक्षी दलों की बैठक भी बुला ली गई है। लेकिन सियासत का असली सवाल यह है कि क्या दिल्ली की एकजुटता उत्तर प्रदेश की जमीन तक पहुंच पाएगी? क्योंकि जिस गठबंधन को दिल्ली में एक मंच पर खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसी गठबंधन के सबसे बड़े चुनावी मैदान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार खुलकर सामने आ रही है।उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग के मुद्दे पर विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने और उन दलों से संवाद बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं, जो हाल के महीनों में कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही INDIA गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाने, संयुक्त प्रेस वार्ता और देशव्यापी साझा आंदोलन की संभावना पर भी बातचीत चल रही है। यानी ऊपर से संदेश यही है कि विपक्ष को फिर एक साथ खड़ा किया जाए।मगर हुजूर, राजनीति में असली परीक्षा मंच पर हाथ मिलाने की नहीं, मैदान में सीट बांटने की होती है। और यहीं से कहानी बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों का हिसाब किताब शुरू होते ही सपा और कांग्रेस के बीच पुरानी दोस्ती की परतें खुरचने लगी हैं। कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी ताकत और पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर बड़ा हिस्सा अपने पास रखना चाहती है। दोनों दल अपने-अपने स्तर पर सीटों की ताकत-कमजोरी का

आकलन कर रहे हैं और गंभीर सीट बंटवारे की बातचीत अक्टूबर में शुरू होने की संभावना बताई गई है।

उधर, तनाव सिर्फ बंद कमरों की बातचीत तक सीमित नहीं है। कांग्रेस के इमरान मसूद ने जल्द गठबंधन तय करने की मांग की और कहा कि भ्रम की स्थिति में कांग्रेस चुनावी तैयारी नहीं कर सकती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो यहां तक कहा कि मतभेद होने पर पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सपा की सांसद इकरा हसन ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने की क्षमता अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। इस तरह यानी एक ही गठबंधन में दो सुर, दो दावे और दो नेतृत्व केंद्र दिखाई दे रहे हैं। चुनावअपडेट्स देखें अखिलेश यादव का रायबरेली से पीडीए यात्रा शुरू करना भी इसी रस्साकशी का हिस्सा माना जा रहा है। रायबरेली कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है, लेकिन अखिलेश ने वहीं से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में जमीन किसके पास है, इसका हिसाब अलग से होगा। इसे कई राजनीतिक विश्लेषक सीट बंटवारे से पहले सपा की राजनीतिक ताकत दिखाने की कवायद के तौर पर देख रहे हैं।

और अब मैनपुरी-इटावा-सैफई की धरती से शिवपाल सिंह यादव का बयान इस खींचतान में नया तड़का लगा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि अखिलेश रायबरेली जा सकते हैं तो कांग्रेस भी इटावा, कन्नौज और मैनपुरी जाएगी। जवाब में शिवपाल ने कहा— जाइए, अभियान चलाइए, लेकिन वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने जसवंतनगर क्षेत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस को वहां वोट न मिलने की बात कही और सपा की जीत का दावा किया।

अब शिवपाल के इस बयान का राजनीतिक मतलब समझिए। यह सिर्फ किसी एक रैली या दौरे पर प्रतिक्रिया नहीं है। यह दरअसल सपा के उस आत्मविश्वास का प्रदर्शन है जिसमें वह कांग्रेस को यह याद दिलाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जमीन सपा के संगठन और सामाजिक आधार से तैयार होती है। मैनपुरी, इटावा और सैफई जैसे इलाकों में कांग्रेस का चुनावी अभियान सपा के लिए सिर्फ सहयोगी दल की गतिविधि नहीं, बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र में दूसरे सहयोगी की राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।

यही INDIA गठबंधन की सबसे बड़ी पहेली है। दिल्ली में सवाल है कौन-कौन साथ आएगा? उत्तर प्रदेश में सवाल है किसके साथ कौन कितनी सीट पर लड़ेगा? दिल्ली में साझा मुद्दे खोजे जा रहे हैं, लखनऊ में सीटों का हिसाब किताब चल रहा है। दिल्ली में एकजुटता की तस्वीर खींची जा रही है और यूपी में दोनों दल अपने-अपने झंडे ऊंचे करने में जुटे हैं। हम आपको याद दिला दें कि 2024 में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने मिलकर 43 लोकसभा सीटें जीती थीं। सपा 37 और कांग्रेस छह पर विजयी रही थी। यही प्रदर्शन अब दोनों दलों के आत्मविश्वास और दावेदारी का आधार बन रहा है। लेकिन 2027 की विधानसभा राजनीति का गणित अलग है। सपा अपने संगठन, सामाजिक समीकरण और विधानसभा में अपनी मौजूदा ताकत के आधार पर ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है, जबकि 2024 के प्रदर्शन और राहुल गांधी की सक्रियता को अपनी बढ़ती राजनीतिक हैसियत का आधार बना रही है।

यानी मामला साफ है। INDIA गठबंधन को जोड़ने की कोशिश दिल्ली में हो रही है, लेकिन उसे बचाने की असली परीक्षा उत्तर प्रदेश में होनी है। क्योंकि गठबंधन सिर्फ नेताओं की मुलाकातों और साझा तस्वीरों से नहीं चलता। गठबंधन तब चलता है जब कार्यकर्ता एक-दूसरे के लिए जमीन छोड़ें, नेता एक-दूसरे की सीमा का सम्मान करें और सीटों के बंटवारे पर दोनों पक्ष अपनी महत्वाकांक्षा को किसी साझा फार्मूले में बांध सकें।

वरना दिल्ली में जितनी बार हाथ मिलेंगे, मैनपुरी और रायबरेली में उतनी ही बार पैर एक-दूसरे की जमीन पर पड़ते दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही पैर कब एक-दूसरे के रास्ते में आ जाएं, इसका फैसला अक्सर दिल्ली की बैठक नहीं, जमीन पर लड़ने वाला कार्यकर्ता करता है।

प्रेरणा

सृजन की राह में चेखव ने चुना था अपना एकांत

महान साहित्यकारों का जीवन अक्सर उनकी रचनाओं जितना ही प्रेरणादायक होता है। वे जिस तरह समाज को देखते हैं, जिस तरह लोगों के बीच रहते हैं और अपने आसपास घट रही घटनाओं को जिस गहराई से महसूस करते हैं, वही उनकी लेखनी को विशिष्ट बनाता है। रूसी साहित्य के महान लेखक एंतोनी चेखव का जीवन भी ऐसी ही सादगी और आत्मसंयम से भरा हुआ था। उन्होंने प्रसिद्धि के शोर से अधिक महत्व उस शांत वातावरण को दिया, जहां वे मनुष्य और जीवन को करीब से समझ सकें। उनके लिए लेखन केवल पेशा नहीं था, बल्कि जीवन को देखने और उसकी सच्चाइयों को समझने का माध्यम था।

चेखव से जुड़ा एक प्रसिद्ध प्रसंग उनके इसी स्वभाव को सामने लाता है। एक बार रूसी साहित्य के विख्यात लेखक मैक्सिम गोर्की ने चेखव से उनकी दिनचर्या और जीवनशैली को लेकर बातचीत की। गोर्की चाहते थे कि चेखव सामाजिक समारोहों, दावतों और साहित्यिक आयोजनों में अधिक सक्रिय रहें। प्रसिद्धि के दौर में लेखकों के लिए ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनना असामान्य बात नहीं थी। साहित्यिक दुनिया में लोगों से मिलना-जुलना, विचारों का आदान-प्रदान करना और सार्वजनिक जीवन में दिखाई देना प्रतिष्ठा का हिस्सा माना जाता था। लेकिन चेखव की प्राथमिकता कुछ और थी।

उन्होंने अपनी सहज शैली में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया। उनका कहना था कि वे एक गुलाम के पोते और एक साधारण दुकानदार के बेटे हैं। उन्होंने जीवन को किसी ऊंचे मंच से नहीं, बल्कि सामान्य लोगों के बीच रहकर जाना था। गरीबी, संघर्ष, मेहनत और साधारण परिवारों की परेशानियां उनके लिए किसी किताब की बातें नहीं थीं। वे इन अनुभवों के बीच से निकले थे। इसलिए प्रसिद्धि मिलने के बाद भी वे अपने मूल जीवनबोध से दूर नहीं होना चाहते थे।

चेखव का मानना था कि एक लेखक के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी संवेदना और स्वतंत्र सोच है। यदि लेखक लगातार बाहरी दिखावे, प्रशंसा और सामाजिक व्यस्तताओं में उलझा रहे, तो उसके भीतर की आवाज कमजोर पड़ सकती है। वे अपने लेखकीय स्वर को बचाए रखना चाहते थे। इसी कारण उन्हें दावतों और समारोहों से अधिक अपना एकांत और अपनी कलम प्रिय थी। उनके लिए शांत कमरा, कागज और विचारों की दुनिया किसी बड़े आयोजन से कम नहीं थी।

गोर्की ने चेखव की इस बात को केवल एक व्यक्तिगत पसंद के रूप में नहीं देखा। वे समझते थे कि यह सादगी ही चेखव की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और उनके व्यक्तित्व की सराहना की। चेखव के भीतर उन्हें एक ऐसा लेखक दिखाई देता था जो प्रसिद्धि के बावजूद अपने मूल स्वभाव से समझौता नहीं कर रहा था। गोर्की स्वयं उनकी प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे और दोनों के बीच की मित्रता रूसी साहित्य के इतिहास में विशेष महत्व रखती है।

चेखव का जीवन अनेक भूमिकाओं से जुड़ा था। वे लेखक होने के साथ चिकित्सक भी थे। चिकित्सा ने उन्हें मनुष्य के शरीर के साथ-साथ उसकी पीड़ा को करीब से देखने का अवसर दिया। अस्पतालों और रोगियों के बीच रहते हुए उन्होंने बीमारी, गरीबी, असहायता और मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा। यही अनुभव उनकी साहित्यिक दृष्टि में उतरते गए। उन्होंने मनुष्य को केवल उसकी सामाजिक पहचान से नहीं देखा, बल्कि उसके भीतर छिपे भय, अकेलेपन, प्रेम, उम्मीद और असफलता को भी समझने की कोशिश की।

उनकी कहानियों में जीवन का कोई असाधारण नायक ही केंद्र में नहीं होता। अक्सर उनके पात्र सामान्य लोग होते हैं। वे छोटे-छोटे सपने देखते हैं, परिस्थितियों से जूझते हैं, रिश्तों में उलझते हैं और कई बार अपनी ही इच्छाओं को पूरा किए बिना जीवन गुजार देते हैं। चेखव ने ऐसे पात्रों के माध्यम से मनुष्य के भीतर की उन भावनाओं को अभिव्यक्ति दी, जिन्हें सामान्यतः लोग शब्दों में नहीं कह पाते।

उनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सहजता थी। वे जीवन के दुख को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करते थे। उनके पात्र रोते हुए दिखाई दें या चुपचाप अपनी पीड़ा सहते रहें, पाठक उनके दर्द को महसूस कर लेता है। यही सूक्ष्मता चेखव की कहानी कला को अलग पहचान देती है। उन्होंने यह साबित किया कि किसी बड़ी घटना के बिना भी एक साधारण जीवन अपने भीतर पूरी कहानी समेटे हो सकता है।

वर्ष 1888 में चेखव को पुश्किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनके साहित्यिक योगदान की महत्वपूर्ण स्वीकृति थी। आगे चलकर उनकी कहानियों और नाटकों ने विश्व साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी रचनाओं में मानवीय मन की जटिलता, सामाजिक परिस्थितियों की विडंबना और जीवन की अनिश्चितता का ऐसा चित्रण मिलता है, जो आज भी पाठकों और साहित्यकारों को आकर्षित करता है। चेखव का जीवन यह संदेश देता है कि रचनाकार के लिए प्रसिद्धि से अधिक महत्वपूर्ण अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता को बचाए रखना है। दुनिया की भीड़ लेखक को पहचान दे सकती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी कलम बनाती है। बाहरी प्रशंसा कुछ समय के लिए उत्साह दे सकती है, मगर लंबे समय तक जीवित रहने वाली रचना उसी संवेदना से पैदा होती है, जिसे लेखक अपने भीतर सुरक्षित रखता है।

आज के समय में जब प्रसिद्धि और सार्वजनिक उपस्थिति को सफलता का महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है, चेखव का जीवन एक अलग दृष्टि प्रस्तुत करता है। उन्होंने दिखाया कि शांत रहकर भी प्रभावशाली हुआ जा सकता है और एकांत में रहकर भी पूरी दुनिया के मनुष्य से संवाद किया जा सकता है। उनका एकांत दुनिया से दूरी नहीं था, बल्कि दुनिया को गहराई से समझने का माध्यम था।

चेखव ने अपने जीवन में सादगी को अपनाया और अपनी कलम को सबसे विश्वसनीय साथी बनाया। उन्होंने सामान्य मनुष्य के जीवन में छिपी असाधारण संवेदनाओं को शब्द दिए। शायद यही कारण है कि उनकी रचनाएं समय की सीमाओं को पार कर आज भी जीवित हैं। उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि सच्चे सृजन के लिए बाहरी शोर नहीं, भीतर की स्पष्टता जरूरी होती है। जब लेखक अपने विचारों और संवेदनाओं के साथ ईमानदार रहता है, तब उसकी कलम एक ऐसी आवाज बन जाती है, जो समय बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों तक पहुंचती रहती है।

UN में Pakistan की जबरदस्त फजीहत, Terrorism पर पूछा गया सवाल तो भाग खड़े हुए Shehbaz Sharif

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आतंकवाद को लेकर सीधे सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा। इसके एक दिन बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के सामने जब पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत पर आतंकवाद प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया, तो जयशंकर ने पलटकर ऐसा करारा जवाब दिया कि सवाल पूछने वाला ही कठघरे में खड़ा हो गया। जयशंकर ने दो टूक कहा, "एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है। चलिए भी।" उधर, जयशंकर के बयान से गर्म हुए माहौल के बीच ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान पर एक और करारा हमला कर डाला।हम आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को एक ''कठपुतली शासन'' करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र में उसके ''झूठ'' और ''छल'' पर तीखा प्रहार किया तथा चेतावनी दी कि इस्लामाबाद की ओर से लगातार जारी आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर मामले को उठाया और 2025 में भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष को रोकने का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ''समय पर हस्तक्षेप'' को दिया। शहबाज शरीफ के संबोधन के बाद भारत ने शुक्रवार रात 'जवाब के अपने अधिकार' का इस्तेमाल किया।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा, ''हमने एक ऐसे शासन से लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवीय मूल्यों पर कुछ पाखंडपूर्ण उपदेश सुने हैं, जिसकी राजधानी को अपने ही लोगों से बचाने के लिए इसी समय किलेबंद किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा, ''और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह सेना का, सेना द्वारा और सेना के लिए शासन है। उसकी कठपुतलियां आती-जाती रह सकती हैं, लेकिन इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि असल में फैसले कौन करता है। पाकिस्तान की वास्तविकता उसके 27वें संविधान संशोधन और उसके असली शासक को दी गई आजीवन कानूनी छूट से जाहिर होती है।'' गहलोत ने पिछले साल नवंबर में शहबाज शरीफ सरकार द्वारा पारित उस 27वें संविधान संशोधन का उल्लेख करते हुए यह बात की जिसके तहत पाकिस्तान के 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी कानूनी मुकदमे से आजीवन छूट दी गई है।

उन्होंने कहा, ''हमें विश्वास है कि यह महासभा पाकिस्तान और उसकी नीतियों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखेगी, न कि उस रूप में जैसे उसके प्रतिनिधि झूठे तरीके से पेश करते हैं। साल-दर-साल झूठ दोहराने से वह सच नहीं हो जाता। पाकिस्तान का आतंकवाद, छल और दोहरा रवैया न तो उसके लिए और न ही दुनिया के लिए फायदेमंद होगा।'' हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में ट्रंप को उनके ''दृढ़तापूर्ण और दूरदर्शी नेतृत्व'' के लिए धन्यवाद देते हुए कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ''समय पर हस्तक्षेप'' ने दक्षिण एशिया में करोड़ों लोगों की जान बचाई। शहबाज शरीफ ने करीब 23 मिनट के अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर मुद्दे का न्यायसंगत और निष्पक्ष समाधान जरूरी है कि दक्षिण एशिया फिर कभी 2025 के संघर्ष जैसी स्थिति में न पहुंचे।

उधर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को याद दिलाया कि शहबाज शरीफ ने ये ''विचित्र टिप्पणियां'' ऐसे समय में की हैं जब महज दो सप्ताह पहले न्यूयॉर्क और दुनिया ने 11 सितंबर के भीषण आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी मनाई थी। गहलोत ने कहा, ''इस संदर्भ को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि उस हमले का मुख्य साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सेना की प्रमुख अकादमी के बिल्कुल पास रह रहा था।'' गहलोत ने शरीफ द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने कहा, ''और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर हमें कश्मीर की ही बात करनी है तो आइए, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर ध्यान देते हैं। रावलाकोट के लोगों से बेमतलब की उन हत्याओं, बर्बर हिंसा और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के बारे में पूछिए जिनका वे लंबे समय से सामना कर रहे हैं।''

हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विवादित सीट को लेकर पिछले कई महीनों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई भी की और हाल में तथाकथित विधानसभा के लिए हुए चुनावों में धांधली के आरोप भी लगे। गहलोत ने सीमा पार आतंकवाद की पाकिस्तान की ''लंबे समय से बरकरार नीति'' की आलोचना करते हुए कहा कि भारत ने पिछले साल दिखा दिया था कि ''आतंकवादियों के पास न भागने की जगह होगी और न छिपने की।'' गहलोत ने कहा, ''हम आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद जारी रहने के परिणाम होंगे। इससे स्वाभाविक रूप से उन व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठेंगे, जिनकी बुनियाद मित्रता और सद्भावना पर रखी गई थी।'' उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ द्वारा व्यक्त किए गए विचार ''ऐसे लोगों की ओर से आए हैं जिनका कट्टरता और नफरत का लंबा इतिहास रहा है।'' गहलोत ने कहा, ''इस महासभा में धार्मिक असहिष्णुता पर उस शासन की ओर से टिप्पणियां की गईं, जिसकी व्यवस्था का एक प्रमुख आधार ईशनिंदा कानून हैं।

अभियान

राम मंदिर चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी, सीसीटीवी में कैद हुईं 105 घटनाएं

अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई जाने वाली दान राशि की गिनती के दौरान कथित हेराफेरी के मामले में विशेष जांच दल की जांच ने कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की करीब 70 हजार पृष्ठों की चार्जशीट में दावा किया गया है कि कथित गबन की गतिविधियां नकदी की गिनती के दौरान हुईं। जांच एजेंसी के अनुसार, यह किसी एक व्यक्ति की कथित करतूत नहीं थी, बल्कि इसमें कई लोगों के बीच समन्वय और संपर्क का एक नेटवर्क सामने आया है। जांच में गिनती केंद्र से नकदी को कथित तौर पर हटाने या छिपाने की 105 घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में कहा गया है कि वे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुईं।

मामले की शुरुआत दान प्रबंधन से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच से हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर 25 जून को मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने चढ़ावे की रकम के संग्रह, गिनती, रखरखाव और बैंक में जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया को खंगालना शुरू किया। एसआईटी ने इस दौरान उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के अलावा डिजिटल उपकरणों, गवाहों के बयानों, बैंक खातों और फॉरेंसिक ऑडिट से प्राप्त जानकारी का भी अध्ययन किया।

चार्जशीट के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज की जांच में ऐसे 105 मौके सामने आए, जिनमें गिनती केंद्र से नकदी को कथित तौर पर निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत हटाने या छिपाने की गतिविधियां दिखाई दीं। जांचकर्ताओं ने इन घटनाओं को केवल वीडियो फुटेज के आधार पर दर्ज नहीं किया, बल्कि उपलब्ध दूसरे साक्ष्यों से उनका मिलान भी किया। एसआईटी का दावा है कि डिजिटल रिकॉर्ड, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल से इन घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया गया।

जांच में यह पहलू भी सामने आया कि गिनी हुई रकम को बैंक तक पहुंचाने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया के दौरान कथित गबन का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके चलते जांच एजेंसी ने कथित अनियमितता का मुख्य केंद्र नकदी की गिनती वाला चरण माना है। चार्जशीट में यह बताया गया है कि गिनती केंद्र पर रकम मौजूद रहने के दौरान ही कथित तौर पर नकदी को अलग करने, छिपाने या बाहर ले जाने की घटनाएं हुईं।

मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला उर्फ शनि, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव के नाम दर्ज हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा को कथित साजिश का मुख्य आरोपी बताया है। हालांकि आरोप पत्र में दर्ज आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में साक्ष्यों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

जांच में डिजिटल साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के मोबाइल फोन से तीन हजार से अधिक हटाए गए संदेश बरामद किए गए। चार्जशीट में दावा किया गया है कि इन संदेशों में कथित तौर पर नकदी को हटाने, छिपाने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और रकम के बंटवारे से संबंधित बातचीत थी। जांच एजेंसी ने इन संदेशों को कथित साजिश से जुड़े डिजिटल साक्ष्य के तौर पर पेश किया है।

चार्जशीट के अनुसार अनुकल्प मिश्रा अपने रिश्तेदार लवकुश मिश्रा और आरोपी अविनाश शुक्ला के साथ टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से संपर्क में था। जांचकर्ताओं ने इन बातचीत के पुराने रिकॉर्ड को तकनीकी प्रक्रिया के जरिए हासिल किया और उनका विश्लेषण किया। एसआईटी ने कथित तौर पर इन संदेशों को सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य जांच सामग्री के साथ जोड़कर आरोपियों की संभावित भूमिका को समझने की कोशिश की।

मामले की आर्थिक जांच भी की गई। जांच एजेंसी ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े बैंक खातों की जानकारी जुटाई। इसके अलावा संपत्तियों, वाहनों और दूसरी परिसंपत्तियों की भी पड़ताल की गई। जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर यह पता लगाने का प्रयास किया कि संदिग्ध रकम का कोई हिस्सा आरोपियों या उनके संपर्क में रहने वाले लोगों तक किस माध्यम से पहुंचा। बैंकिंग रिकॉर्ड और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को जांच का हिस्सा बनाया गया।

पुलिस ने आठ आरोपियों में से सात से कथित तौर पर 79.85 लाख रुपये बरामद करने का दावा किया है। चार्जशीट के अनुसार सुभाष श्रीवास्तव से इस मामले में कथित गबन की रकम की कोई बरामदगी नहीं हुई। अलग-अलग आरोपियों से मिली रकम का भी जांच दस्तावेज में विवरण दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपये बरामद हुए। लवकुश मिश्रा के पास से करीब 14.25 लाख रुपये मिलने का दावा किया गया है। अविनाश शुक्ला से 20.39 लाख रुपये के अलावा 1,121 अमेरिकी डॉलर बरामद होने की बात कही गई है। रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपये, करुणेश पांडे से 18.07 लाख रुपये और मनीष यादव से दो लाख रुपये बरामद किए जाने का उल्लेख है। कुछ आरोपियों से सोने-चांदी के सामान मिलने का दावा भी जांच दस्तावेजों में किया गया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, नकदी की कथित हेराफेरी से जुड़े घटनाक्रम को समझने में सीसीटीवी फुटेज सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक रहा। गिनती केंद्र पर किस समय कौन मौजूद था, नकदी के साथ किस तरह की गतिविधियां हुईं और उसके बाद रकम की स्थिति क्या रही, इन सभी पहलुओं को फुटेज के माध्यम से खंगाला गया। इसके बाद संबंधित लोगों के बयान और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ घटनाओं का मिलान किया गया।

इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि मंदिर में श्रद्धालुओं से प्राप्त होने वाली दान राशि की गिनती और उसके सुरक्षित प्रबंधन की व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में अपनी श्रद्धा के अनुसार धन और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। ऐसे में दान की गिनती, रिकॉर्डिंग, सत्यापन और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी का विशेष महत्व है।

एसआईटी की चार्जशीट में जिन 105 घटनाओं का उल्लेख किया गया है, वे जांच एजेंसी के अनुसार कथित तौर पर नकदी हटाने या छिपाने से जुड़ी हैं। इन घटनाओं को लेकर अदालत में साक्ष्यों की जांच होगी और आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को तब तक अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता, जब तक न्यायालय में वे साबित न हो जाएं।

फिलहाल करीब 70 हजार पृष्ठों की चार्जशीट में दर्ज सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल संदेश, बैंकिंग रिकॉर्ड, कथित नकदी बरामदगी और गवाहों के बयानों ने मामले को विस्तृत जांच के दायरे में ला दिया है। एसआईटी ने इन सभी कड़ियों को जोड़कर कथित गबन की पूरी तस्वीर अदालत के सामने रखने का प्रयास किया है। अब न्यायिक प्रक्रिया के दौरान यह तय होगा कि जांच में जुटाए गए साक्ष्य आरोपों को किस सीमा तक प्रमाणित करते हैं और आरोपियों की वास्तविक भूमिका क्या थी। मामला सामने आने के बाद मंदिर की दान राशि की गिनती और प्रबंधन व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी व्यापक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

बारिश ने कई राज्यों में रोकी जिंदगी की रफ्तार, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा स्थगित; झारखंड में नदियां उफान पर

नई दिल्ली। सितंबर के अंतिम दिनों में देश के कई हिस्सों में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण जलभराव, नदियों के बढ़ते जलस्तर, सड़क बाधित होने और फसलों को नुकसान जैसी स्थिति सामने आई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। वहीं झारखंड में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरने से सामान्य आवाजाही प्रभावित हुई है। ओडिशा में भारी बारिश के कारण हजारों लोगों को राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया।

उत्तराखंड में खराब मौसम का सबसे अधिक असर पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 26 और 27 सितंबर के लिए राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शनिवार को बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट रहा। रविवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के लिए रेड अलर्ट तथा कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई है।

मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चारधाम यात्रा को शनिवार दोपहर से 27 सितंबर तक स्थगित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़कें बाधित होने, नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ने तथा अचानक जलभराव का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम सामान्य होने के बाद यात्रा फिर शुरू करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने तथा सड़क मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका के बीच यात्रियों और स्थानीय लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने को कहा गया है। कई जिलों में स्कूलों को भी एहतियातन बंद रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश और तेज हवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के कई हिस्सों में खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। भारी बारिश के कारण अनेक स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में राज्य में सामान्य से करीब 19 गुना अधिक बारिश दर्ज की गई। कई जिलों में तेज हवा और बारिश के कारण मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सितंबर के अंतिम दौर में हुई लगातार बारिश से खेतों में खड़ी फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

राज्य में प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जलभराव वाले इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश के कारण ग्रामीण सड़कों और संपर्क मार्गों पर भी असर पड़ने की आशंका है। खेतों में पानी जमा होने से फसल नुकसान का आकलन भी महत्वपूर्ण हो गया है। झारखंड में बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और कई जगह वाहन पानी में फंस गए। कुछ इलाकों में लोगों को घुटने तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। पूर्वी सिंहभूम जिले में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से 2.02 मीटर ऊपर बह रही थी, जबकि खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4.50 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और जरूरत पड़ने पर ऊंचे तथा सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। रांची में भी लगातार बारिश के कारण बांधों का जलस्तर बढ़ा है। हटिया और गेतलसूद बांधों में पानी का स्तर लगातार ऊपर गया है। खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा और बिरसा मुंडा हवाईअड्डे से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। रांची, जमशेदपुर सहित कई जिलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों में कक्षाएं स्थगित की गईं। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश लाने वाली प्रणाली के कमजोर पड़ने के साथ राज्य में मौसम की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार की संभावना है, लेकिन तब तक संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है।

ओडिशा में भी भारी बारिश ने कई जिलों में जनजीवन प्रभावित किया। राज्य में सक्रिय गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण व्यापक बारिश हुई। कई स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। नबरंगपुर जिले के तेंतुलीखुंटी में 395 मिलीमीटर, नंदाहांडी में 344 मिलीमीटर और कोरापुट जिले के बोरीगुमा में 307.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अत्यधिक बारिश के कारण कई इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया तथा भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ। दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के प्रभावित इलाकों से करीब 14,500 लोगों को सुरक्षित निकालकर 2,061 राहत केंद्रों में पहुंचाया गया। प्रशासन ने राहत शिविरों में भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है। कई स्थानों पर सड़क और रेल सेवाओं पर भी मौसम का असर पड़ा। भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं ने प्रशासन के सामने अतिरिक्त चुनौती खड़ी कर दी है। प्रभावित इलाकों में स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश के कारण प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने पड़े। जलभराव, नदियों और नालों के बढ़ते जलस्तर तथा आवागमन में आ रही परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने 26 सितंबर को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। जिला प्रशासन को बाढ़ और जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। निचले इलाकों पर विशेष निगरानी रखने तथा जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा गया है। प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल, दवाइयों और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को मौसम की स्थिति के अनुसार सतर्क किया जाए। लगातार बारिश के दौरान ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में संपर्क प्रभावित होने की स्थिति में राहत दलों की तैनाती भी महत्वपूर्ण हो गई है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश का असर तापमान पर भी पड़ा। राजधानी में बारिश के बाद मौसम अपेक्षाकृत ठंडा हुआ और तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। सफदरजंग मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के कारण राजधानी में गर्मी से राहत मिली और हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही।

सफाई कार्यों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए 4 अक्टूबर को सूरत में नेताओं की एक विशाल बैठक हुई

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

गुजरात राज्य में वाल्मीकि, नादिया और मेघवाड़ समुदाय स्वच्छता कार्यों से जुड़े हुए हैं। वर्षों पहले, वाल्मीकि समुदाय के लोग सिर पर कूड़ा उठाकर सफाई का काम करते थे। इस समुदाय के अधिकांश लोगों की आजीविका स्वच्छता कार्य पर निर्भर है। अब सरकार ने ठेका प्रणाली लागू करके इस समुदाय को भुखमरी की ओर धकेलने का प्रयास शुरू कर दिया है। हम राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारों के लाभ के लिए शुरू की गई इस ठेका प्रणाली की कड़ी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि गुजरात सरकार राज्य से स्वच्छता कार्यों की ठेका प्रणाली को समाप्त करे। 10 अप्रैल, 2026 को सूरत में स्वच्छता कार्यों में लगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। सूरत के वाल्मीकि समुदाय के नेता भाई लाल बी. ने बताया कि इस बैठक में पूरे गुजरात से स्वच्छता कार्यों की ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए आगे की योजनाओं पर निर्णय लिया जाएगा। वैष्णव, जयंतीभाई वाघेला, शशिकांतभाई सोलंकी, प्रवीणभाई पटेल, किरीटभाई वाघेला, इकबालभाई शेख, हरीशभाई राठौड़ और विजयभाई शेनमेरे ने एक बयान में यह बात कही है।

हरीश रावत की हरिद्वार वाली इच्छा पर त्रिवेंद्र का क्रिकेट वाला तंज, बोले- गुगली किसका स्टंप उड़ाएगी कहना मुश्किल

हरिद्वार से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताने के बाद बढ़ी सियासी हलचल, भाजपा सांसद बोले- चुनाव लड़ना कांग्रेस और हरीश रावत का विषय

हरिद्वार। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की ओर से हरिद्वार जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताए जाने के बाद अब भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हरिद्वार से भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत के बयान पर क्रिकेट के अंदाज में तंज कसते हुए उन्हें 'गुगली मास्टर' बताया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की गुगली किस दिशा में जाएगी और किसका स्टंप उड़ा देगी, यह पहले से कहना मुश्किल है। उनकी इस टिप्पणी के बाद हरिद्वार की सियासत में बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है।

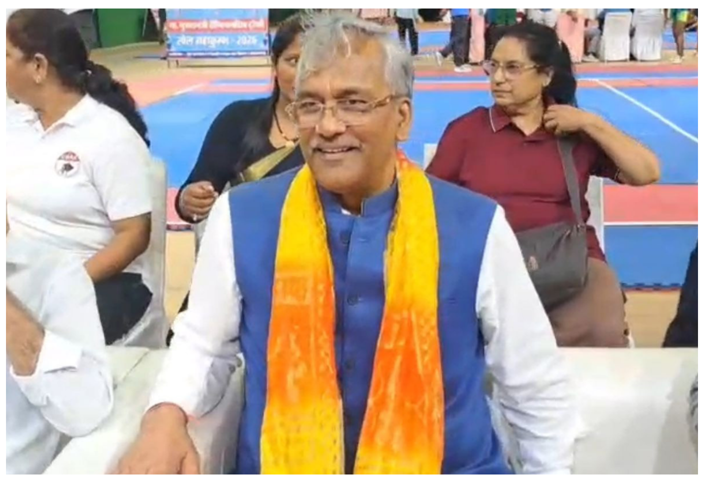

हरिद्वार में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब हरीश रावत की चुनावी इच्छा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना या लड़ाना कांग्रेस और हरीश रावत का अपना विषय है। उन्होंने हरीश रावत के लिए अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में हरीश रावत की सक्रियता स्वाभाविक है और उन्हें राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए। हालांकि इसी के साथ उन्होंने क्रिकेट की भाषा में उनकी राजनीतिक रणनीति पर चुटकी लेते हुए कहा कि वह 'गुगली मास्टर' हैं और उनकी गेंद किस दिशा में जाकर किसका स्टंप उड़ा देगी, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। दरअसल, हरीश रावत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के माध्यम से हरिद्वार से विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने वर्ष 2009 से 2014 तक हरिद्वार का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा था कि यह उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण दौर रहा। उन्होंने हरिद्वार से अपने पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि समय बीतने के साथ इस क्षेत्र से उनका संबंध और गहरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मन में हरिद्वार को लेकर कई योजनाएं और विचार हैं तथा वह क्षेत्र को उत्तराखंड के लिए मजबूत आधार के रूप में विकसित करने में योगदान देना चाहते हैं।

हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में यह भी संकेत दिया कि हरिद्वार के लोगों में एक वर्ग की इच्छा है कि वह एक बार फिर विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राज्य के व्यापक राजनीतिक सवालों और पार्टी के आंतरिक विषयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी इस इच्छा पर विचार करना पड़ता है। इस वजह से उनके बयान को तत्काल चुनावी घोषणा के बजाय चुनाव लड़ने की इच्छा और संभावित राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अभी हरिद्वार जिले की किसी एक विधानसभा सीट को अंतिम रूप से घोषित नहीं किया है।

हरीश रावत का हरिद्वार से राजनीतिक रिश्ता पुराना है। वह 2009 से 2014 के बीच हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रहे। इसी कार्यकाल को वह अपने राजनीतिक जीवन का बेहद महत्वपूर्ण दौर बता चुके हैं। हरिद्वार में लंबे समय तक सक्रिय रहने के दौरान उनके क्षेत्र के लोगों से व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध भी बने। इसी पुराने जुड़ाव का हवाला देते हुए उन्होंने हाल में एक बार फिर विधानसभा के जरिए हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जताई है।

हरीश रावत के इस बयान के बाद उनके हरिद्वार दौरे ने भी राजनीतिक चर्चा को बढ़ाया। हाल में उन्होंने हरकी पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में अपनी बात रखी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव लड़ना या अंतिम फैसला समय, परिस्थितियों, उम्र और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए किया जाएगा। उन्होंने व्यक्तिगत इच्छा के तौर पर यह भी कहा कि वह जीवन के अंतिम समय में खुद को हरिद्वार के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत की 'गुगली' वाली टिप्पणी ने राजनीतिक चर्चा को नया रंग दे दिया है। क्रिकेट में गुगली ऐसी गेंद को कहा जाता है जिसकी दिशा बल्लेबाज को अनुमान से अलग दिखाई देती है। इसी क्रिकेट शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए त्रिवेंद्र रावत ने हरीश रावत की राजनीतिक शैली पर टिप्पणी की। उनका आशय यह था कि हरीश रावत की अगली राजनीतिक चाल या चुनावी दिशा का अनुमान लगाना आसान नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चुनावी मैदान में कौन प्रभावित होगा, इसका फैसला राजनीतिक परिस्थितियां ही करेंगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद हैं। लोकसभा के मौजूदा कार्यकाल के आधिकारिक संसदीय रिकॉर्ड में भी उनका निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार और पार्टी भाजपा दर्ज है। दूसरी ओर हरीश रावत के हरिद्वार से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा ने दोनों नेताओं के पुराने राजनीतिक क्षेत्र को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस उन्हें हरिद्वार जिले की किस विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगी या उनकी दावेदारी को पार्टी किस रूप में आगे बढ़ाएगी।

हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में हरिद्वार क्षेत्र से रावत परिवार का राजनीतिक जुड़ाव पहले से रहा है। अब स्वयं हरीश रावत के विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताने के बाद कांग्रेस के भीतर भी संभावित चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चा स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। हालांकि टिकट का अंतिम निर्णय पार्टी स्तर पर ही होगा।

उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सक्रियता बढ़ रही है। हरीश रावत पहले भी यह कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा, उसके अनुसार वह काम करेंगे। ऐसे में हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा का उनका ताजा बयान उनके राजनीतिक भविष्य और आगामी चुनाव में उनकी संभावित भूमिका को लेकर चर्चा का नया आधार बना है।

भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी तैयारियां आगे बढ़ने के साथ हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में नेताओं के बयानों पर नजर रहना तय है। फिलहाल हरीश रावत ने अपनी इच्छा सार्वजनिक की है, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस पर राजनीतिक व्यंग्य के अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं के बयानों के बीच यह बात साफ है कि चुनावी मैदान में उतरने का अंतिम फैसला संबंधित दलों और उम्मीदवारों की औपचारिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

हरिद्वार में फिलहाल चर्चा इस बात को लेकर है कि हरीश रावत की यह इच्छा आगे किस राजनीतिक रूप में सामने आती है। क्या वह स्वयं चुनावी मैदान में उतरेंगे, किस विधानसभा सीट से दावेदारी करेंगे और कांग्रेस इस संबंध में क्या निर्णय लेगी, इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। दूसरी ओर त्रिवेंद्र सिंह रावत की 'गुगली' वाली टिप्पणी ने इस राजनीतिक घटनाक्रम को जरूर दिलचस्प बना दिया है। अब हरिद्वार की राजनीति में आने वाले दिनों में नेताओं के अगले बयानों और पार्टी स्तर पर होने वाले फैसलों पर नजर रहेगी।

TTE की सतर्कता से यात्री का 60,000 का लैपटॉप सहित बैग सुरक्षित वापस

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में यात्री सेवा, सतर्कता एवं ईमानदारी का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। दिनांक 25 सितंबर 2026 को ट्रेन संख्या 19119 में ऑन ड्यूटी TTE/वेरावल श्री रामजीवन कुमार ने यात्री द्वारा ट्रेन में छूटे बैग को सुरक्षित रखकर उसे उसके वास्तविक स्वामी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यात्री राजकोट से जूनागढ़ तक यात्रा कर रहे थे। जूनागढ़ स्टेशन पर उतरते समय जल्दबाजी में वे अपना बैग ट्रेन की सीट संख्या C-1/55 पर भूल गए। बाद में यात्री को बैग छूटने का पता चला और उन्होंने फोन के माध्यम से इसकी सूचना TTE श्री रामजीवन कुमार को दी। सूचना मिलते ही श्री रामजीवन कुमार ने तत्परता दिखाते हुए बैग को सुरक्षित अपने पास रख लिया।

बैग में लगभग 60,000 मूल्य का Dell Laptop, 2,500 नकद, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण सामान मौजूद था। यात्री की ID एवं टिकट से आवश्यक सत्यापन के पश्चात बैग सुरक्षित रूप से यात्री को वापस कर दिया गया।

अपना महत्वपूर्ण सामान सुरक्षित वापस मिलने पर यात्री ने श्री रामजीवन कुमार एवं पश्चिम रेलवे के प्रति आभार व्यक्त किया तथा उनकी तत्परता एवं ईमानदारी की सराहना की।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने TTE/वेरावल श्री रामजीवन कुमार के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यात्रियों के छूटे हुए सामान को सुरक्षित उनके वास्तविक स्वामियों तक पहुंचाना यात्री सेवा, संवेदनशीलता एवं सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा ने भी इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास रेलवे कर्मचारियों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं यात्री सेवा के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करते हैं।

पश्चिम रेलवे यात्रियों की सेवा, सुरक्षा एवं विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित, सुखद एवं सुविधाजनक रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

चार बड़े बंदरगाहों को मिला 'मेगा पोर्ट' का दर्जा, समुद्री व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार

नई दिल्ली। भारत के समुद्री व्यापार और परिवहन ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने देश के चार प्रमुख बंदरगाहों को 'मेगा पोर्ट' के रूप में अधिसूचित किया है। इस सूची में गुजरात का मुंद्रा पोर्ट भी शामिल है, जो अब तक गैर-प्रमुख बंदरगाह की श्रेणी में आता था। इसके अलावा दीनदयाल पोर्ट यानी कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और ओडिशा का पारादीप पोर्ट भी 'मेगा पोर्ट' के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस वर्गीकरण से देश के समुद्री बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय बंदरगाहों की क्षमता को और विस्तार दिया जा सकेगा।

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 की धारा 73 की उप-धारा (1) के तहत जारी की गई है। मंत्रालय के अनुसार, जिन बंदरगाहों को 'मेगा पोर्ट' का दर्जा दिया गया है, उन्होंने इसके लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है। नए वर्गीकरण के साथ इन बंदरगाहों की भूमिका देश के समुद्री माल परिवहन और वैश्विक व्यापार नेटवर्क में और महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। दीनदयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और पारादीप पहले से ही देश के प्रमुख बंदरगाहों में शामिल रहे हैं। इन बंदरगाहों पर लंबे समय से बड़े पैमाने पर माल की आवाजाही होती रही है। दूसरी ओर गुजरात का मुंद्रा पोर्ट अब तक गैर-प्रमुख बंदरगाह की श्रेणी में था। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित इस बंदरगाह को 'मेगा पोर्ट' की श्रेणी में शामिल किए जाने को भारतीय समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और ढांचागत बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। देश में इस समय 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाह संचालित हैं। प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जबकि गैर-प्रमुख बंदरगाहों का संचालन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों या राज्य समुद्री बोर्डों के अधिकार क्षेत्र में होता है। भारतीय समुद्री व्यापार के विस्तार के साथ इन बंदरगाहों पर माल की आवाजाही लगातार बढ़ी है। ऐसे में बड़े और उच्च क्षमता वाले बंदरगाहों को अलग श्रेणी में चिन्हित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। 'मेगा पोर्ट' का दर्जा दिए जाने के पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य देश में बड़े पैमाने पर समुद्री माल परिवहन की क्षमता को बढ़ाना और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बड़े आकार के जहाजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे जहाजों के लिए गहरे जल वाले बंदरगाह, आधुनिक टर्मिनल, पर्याप्त भंडारण सुविधा और तेज माल निकासी की व्यवस्था आवश्यक होती है। भारत के लिए भी बड़े जहाजों को सीधे अपने बंदरगाहों तक आकर्षित करना व्यापार लागत और परिवहन समय को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। चार बंदरगाहों को मेगा पोर्ट की श्रेणी में शामिल किए जाने से कंटेनर, थोक माल, ऊर्जा उत्पादों और अन्य औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। इससे बंदरगाहों पर माल की आवाजाही को अधिक व्यवस्थित और तेज बनाने के लिए आधुनिक तकनीक तथा लॉजिस्टिक सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही बंदरगाहों को सड़क, रेल और अंतर्देशीय परिवहन नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ने की जरूरत भी बढ़ेगी, ताकि बंदरगाह तक पहुंचने और वहां से माल को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में समय कम हो। मुंद्रा पोर्ट का इस सूची में शामिल होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित मुंद्रा देश के प्रमुख निजी बंदरगाहों में से एक है और बड़े पैमाने पर कार्गो तथा कंटेनर संचालन से जुड़ा है। इसके मेगा पोर्ट के रूप में अधिसूचित होने से निजी क्षेत्र के बंदरगाहों की बढ़ती भूमिका भी सामने आती है। समुद्री व्यापार में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के बंदरगाहों की क्षमता का इस्तेमाल भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकता है।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे न्हावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी तट पर कंटेनर परिवहन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। मुंबई क्षेत्र की औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों से इसका सीधा संबंध है। वहीं दीनदयाल पोर्ट गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के लिए समुद्री माल परिवहन का महत्वपूर्ण माध्यम है। पारादीप पोर्ट पूर्वी तट पर स्थित होने के कारण खनिज, औद्योगिक कच्चे माल और अन्य वस्तुओं के समुद्री परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह चारों बंदरगाह देश के अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों और व्यापारिक गलियारों को जोड़ते हैं। सरकार के समुद्री बुनियादी ढांचे को विस्तार देने के प्रयासों में बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ जहाजों के ठहराव का समय कम करना, माल की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करना और लॉजिस्टिक लागत घटाना भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। किसी देश की निर्यात क्षमता केवल उत्पादन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक कम समय और कम लागत में पहुंचाने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आधुनिक बंदरगाह भारत की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाला प्रमुख आधार बन सकते हैं।

'मेगा पोर्ट' के रूप में वर्गीकरण से इन बंदरगाहों की क्षमता और उपयोगिता को राष्ट्रीय समुद्री नीति के व्यापक लक्ष्य से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। भारत लंबे समय से अपने समुद्री व्यापार के विस्तार और बंदरगाह आधारित विकास पर जोर देता रहा है। देश की लंबी समुद्री तटरेखा और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बंदरगाहों का रणनीतिक और आर्थिक महत्व काफी अधिक है। समुद्री मार्गों के माध्यम से होने वाला अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और इसके विस्तार के लिए मजबूत बंदरगाह नेटवर्क आवश्यक है। नए वर्गीकरण के साथ यह भी उम्मीद की जा रही है कि बंदरगाहों पर आधुनिक तकनीक, स्वचालित प्रणालियों और डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेज होगा। इससे जहाजों की आवाजाही, कार्गो प्रबंधन, दस्तावेजी प्रक्रियाओं और माल की निकासी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। हालांकि 'मेगा पोर्ट' का दर्जा अपने आप में सभी सुविधाओं के विस्तार की गारंटी नहीं है। वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि इन बंदरगाहों की क्षमता, संपर्क व्यवस्था, तकनीकी सुविधाओं और लॉजिस्टिक नेटवर्क को किस तरह विकसित किया जाता है। चार बंदरगाहों को एक साथ इस श्रेणी में शामिल किए जाने से भारत के समुद्री व्यापार ढांचे में क्षेत्रीय संतुलन का पहलू भी दिखाई देता है। पश्चिमी तट पर दीनदयाल और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तथा मुंद्रा और पूर्वी तट पर पारादीप जैसे बड़े केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े व्यापार को समुद्री मार्ग उपलब्ध कराते हैं। इससे निर्यातकों और आयातकों के लिए वैकल्पिक मार्ग और बेहतर बंदरगाह सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

डीआरएम श्री दिनेश वर्मा ने वेरावल रनिंग रूम एवं स्टेशन का निरीक्षण कर कर्मचारी सुविधाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री दिनेश वर्मा ने दिनांक 26 सितंबर, 2026 को वेरावल रनिंग रूम एवं वेरावल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य रेल परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करने के साथ-साथ निर्माणाधीन नए रनिंग रूम के कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लेना था।

निरीक्षण के दौरान डीआरएम श्री वर्मा ने लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर के लिए उपलब्ध विश्राम एवं ठहरने की सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों को ड्यूटी के बाद पर्याप्त एवं आरामदायक विश्राम सुविधा उपलब्ध कराने तथा रनिंग रूम में स्वच्छता, रख-रखाव, पेयजल, प्रकाश, भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

डीआरएम ने निर्माणाधीन नए रनिंग रूम का भी निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री, कार्य की गुणवत्ता एवं विभिन्न सुविधाओं के प्रावधानों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को विकसित करने के निर्देश दिए।

वेरावल स्टेशन के निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन परिसर एवं यात्री सुविधाओं से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया।

डीआरएम ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों का बेहतर स्वास्थ्य, पर्याप्त विश्राम एवं कल्याण सुरक्षित और सुचारु रेल परिचालन के महत्वपूर्ण आधार हैं। इस दिशा में भावनगर मंडल द्वारा कर्मचारी सुविधाओं एवं यात्री सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान मंडल के विभिन्न शाखाधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में भावनगर मंडल का एक और महत्वपूर्ण कदम

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने रेल दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं सुरक्षित ट्रेन परिचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मंडल द्वारा मौजूदा Control Communication Equipment for Optical Fiber Communication (OFC) using 2-wire Telephones (CCEO) आधारित ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन प्रणाली को अत्याधुनिक Multi Protocol Label Switching Voice Over Internet Protocol (MPLS VoIP) आधारित ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम (TCCS) में सफलतापूर्वक माइग्रेट किया गया है। इससे संबंधित रेलखंडों में ट्रेन परिचालन के दौरान संचार व्यवस्था अधिक आधुनिक, विश्वसनीय एवं प्रभावी होगी।

इस तकनीकी उन्नयन के तहत Level Switching Router Internet Protocol / Label Edge Router (LSR/LER) आधारित IP-MPLS बैकबोन नेटवर्क दो प्रमुख रेलखंडों में स्थापित किया गया है। इसमें ढसा–जेतलसर–वांसजालिया मुख्य लाइन पर 195 किलोमीटर तथा पोरबंदर–कानालुस मुख्य लाइन पर 106 किलोमीटर, कुल 301 किलोमीटर रेलखंड एवं 23 स्टेशनों को आधुनिक नेटवर्क से जोड़ा गया है। नवीन VoIP आधारित ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम (TCCS) के माध्यम से स्टेशन मास्टर, ट्रेन कंट्रोलर एवं लोको पायलट के बीच संचार को अधिक तेज, स्पष्ट एवं सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। इससे ट्रेन परिचालन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान तथा परिचालन में संचार की विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि Multi Protocol Label Switching (MPLS) नेटवर्क को इसकी स्थिरता एवं कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक माह की निगरानी अवधि के लिए सेवा में लिया गया है। सफल निगरानी के उपरांत अन्य डिजिटल एवं दूरसंचार सेवाओं को भी चरणबद्ध रूप से इस आधुनिक नेटवर्क पर माइग्रेट किया जाएगा। इससे भविष्य की डिजिटल सेवाओं के लिए एक मजबूत तकनीकी आधार तैयार होगा।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में भावनगर मंडल द्वारा रेल परिचालन में आधुनिक तकनीक को अपनाने एवं यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा तथा बेहतर सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कार्य सीनियर डिविजनल सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर (Sr. DSTE) श्री एच. एस. आर्या के नेतृत्व में सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गांधीधाम में 2300 करोड़ रुपए के 150 टीपीडी क्षमता वाले ई-मेथनॉल प्लांट का शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- कंडला का ई-मेथनॉल प्रोजेक्ट आगामी समय में भारत के ग्रीन एनर्जी के विजन को देगा नई दिशा
- ई-मेथनॉल प्रोजेक्ट गुजरात की मैरीटाइम ताकत और असम की औद्योगिक क्षमता का संयोजन है
- दीनदयाल पोर्ट केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि देश का अहम समुद्री प्रवेशद्वार
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन शिपिंग जैसी नई ऊर्जा व्यवस्थाओं की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है
- कभी चुनौतियों की भूमि के तौर पर जाने जाने वाले कच्छ की पहचान बदलने का काम प्रधानमंत्री ने किया

असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा

- गुजरात सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में देश की अगुवाई कर रहा है
- गुजरात के सपूत और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कारण असम के विकास को मिली एक नई दिशा
- गुजरात इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई राज्य सक्षमता से देश के विकास में योगदान दे सकता है

▶▶ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन गया है : केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल

▶▶ 150 टीपीडी क्षमता के ई-मेथनॉल प्लांट के कार्यान्वित होने से स्थानीय स्तर पर 3500 से अधिक प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार का सृजन होगा

▶▶ दीनदयाल पोर्ट और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम से ग्रीन शिपिंग क्षेत्र में आएगी नई क्रांति

▶▶ ई-मेथनॉल ग्रीन फ्यूल उत्पादन के साथ गुजरात सहित कच्छ के औद्योगिक विकास और रोजगार को मिलेगी एक नई दिशा

▶▶ गुजरात और असम की औद्योगिक भागीदारी से कच्छ में टिकाऊ बंदरगाह विकास के लक्ष्य के साथ 2300 करोड़ रुपए के ग्रीन ई-मेथनॉल प्रोजेक्ट का शिलान्यास

गांधीनगर : गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कच्छ के गांधीधाम में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कंडला और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम से आकार लेने वाले 150 टीपीडी (टन प्रतिदिन) क्षमता वाले ई-मेथनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। गांधीधाम में 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम गांधीधाम के डीपीए एग्जीबिशन ग्राउंड में आयोजित हुआ। यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत के ग्रीन एनर्जी के विजन को एक नई दिशा देगा। प्रोजेक्ट के शिलान्यास अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शिलान्यास अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रसेवा, समर्पण और जनसेवा साधना के 25 वर्ष 7 अक्टूबर को पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार और सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने का अनूठी रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस सफलता को लोगों तक पहुंचाने के लिए देशभर में 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित हो रहा है।

ई-मेथनॉल प्लांट के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज कच्छ की धरती पर दीनदयाल पोर्ट में देश के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन शिपिंग को नई दिशा देने वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो रहा है। यह प्रोजेक्ट गुजरात की मैरीटाइम स्ट्रैंथ यानी समुद्री ताकत और असम की औद्योगिक क्षमता का संयोजन है और यह प्रधानमंत्री के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' विजन को प्रतिबिंबित करता है।

मुख्यमंत्री ने दीनदयाल पोर्ट को केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि देश का एक अहम समुद्री प्रवेशद्वार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन शिपिंग जैसी नई ऊर्जा व्यवस्थाओं की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत कच्छ में दीनदयाल पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। कच्छ के कंडला में ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। इस इकोसिस्टम में असम पेट्रो-केमिकल्स के ई-मेथनॉल का एक महत्वपूर्ण जुड़ाव हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट के विजन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत केवल इसके निवेश में नहीं, बल्कि इसके पीछे मौजूद पर्यावरणीय संकल्प में भी है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री की पंचामृत घोषणा के माध्यम से 2070 तक नेट-जीरो की ओर आगे बढ़ने के संकल्प के विजन को स्पष्ट करता है। आज देश में पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि 27 सितंबर यानी कल रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह देश की पहली एलएनजी ट्रेन को साबरमती से रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेलवे द्वारा क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में यह एक ठोस कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कंडला दीनदयाल पोर्ट में बनने वाला ई-मेथनॉल प्लांट प्रधानमंत्री की ग्रीन ग्रोथ की प्रतिबद्धता को चरितार्थ करता है। भारत का ज्यादातर व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। इस कारण पोर्ट और शिपिंग का डीकार्बोनाइजेशन भी जलवायु लक्ष्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कंडला में ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन और बंकरिंग फैसिलिटी तैयार होने से जहाजों को स्वच्छ मरीन फ्यूल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा।

कच्छ के औद्योगिक विकास का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कच्छ की उस पहचान को बदलने का काम किया है, जो कभी चुनौतियों की भूमि के रूप में जानी जाती थी। कच्छ में एशिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। आज कच्छ में इंडस्ट्री, पोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ-साथ ग्रीन फ्यूल का एक नया अध्याय जुड़ रहा है। यह ई-मेथनॉल प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के विजन को मजबूत करने के साथ ही यह साबित भी करता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने 'मिशन लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) की अपनी अवधारणा में भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को लोगों की दैनिक जीवनशैली और सामूहिक प्रयासों से जोड़ा है। कंडला का यह प्रोजेक्ट मिशन लाइफ के व्यापक विचार के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ने, संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण तैयार करने का मंत्र भी दिया है।

अंत में, मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अनुरोध किया कि हम सभी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत 2047 के संकल्प में सहभागी बनें। हम स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने दोनों राज्यों के औद्योगिक समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि यह ई-मेथनॉल प्रोजेक्ट देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि है। इस प्रोजेक्ट का आने वाले दिनों में और विस्तार होगा और यह देश-विदेश के जहाजों के लिए जरूरी ईंधन एवं ऊर्जा को ग्रीन मेथनॉल में रूपांतरित करने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2021 में ग्लासगो में आयोजित कॉप-26 समिट के '2070 तक नेट जीरो' लक्ष्य का उल्लेख करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करके ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने का नया उत्साह शुरू हुआ है। गुजरात सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत दुनिया में मजबूती से उभर रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने गुजरात और असम के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को याद करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के समय से ही दोनों राज्यों के संबंध मजबूत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत के सर्वांगीण विकास और सेमीकंडक्टर प्लांट जैसी परियोजनाओं के लिए उन्होंने गुजरात के सपूत और देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कारण ही असम के विकास को एक नई दिशा मिली है।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गुजरात के जरिए असम को देश के विकास में भागीदार बनने का अवसर मिल रहा है। आज गुजरात इस बात का शानदार उदाहरण बन गया है कि कैसे कोई राज्य देश के विकास में सक्षमता से योगदान दे सकता है। गुजरात मॉडल से प्रेरणा लेकर असम सरकार इसे अनेक परियोजनाओं में लागू कर रही है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गत 12 वर्षों से 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन के अंतर्गत देश की जनता को एकजुट करके भारत माता की सेवा में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन गया है। ई-मेथनॉल प्लांट से असम और गुजरात के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित होगा और यह भारत सरकार के संस्थानों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।

कच्छ एवं गुजरात के समुद्री व्यापार के 5000 वर्ष पुराने इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वित होने से नई पीढ़ी के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे और वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशालीऔर विकसित देश बनाने के संकल्प को नया बल मिलेगा।

पोर्ट की क्षमता और विजन के बारे में जानकारी देते हुए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन श्री सुशील कुमार सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ग्रीन एनर्जी के विजन के साकार करने का अवसर है। उन्होंने ई-मेथनॉल प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और गुजरात सरकार का आभार व्यक्त किया।

असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष श्री बिकुल डेका ने स्वागत भाषण में कहा कि ई-मेथनॉल प्लांट आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करके भारत में ही जहाजों के ईंधन (शिप फ्यूल) के उत्पादन की नई दिशा खोलेगा। होर्मुज स्ट्रेट जैसे संकट की स्थिति में भी घरेलू ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के टेक्निकल अनुभव और गुजरात के पोर्ट डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर का संयोजन देश के विकास में विशेष भूमिका निभाएगा।

ई-मेथनॉल 150 टीपीडी क्षमता और रोजगार सृजन से गुजरात सहित कच्छ को मिलेगी नई औद्योगिक दिशा

2300 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी निवेश के साथ कंडला में स्थापित होने वाला यह 150 टीपीडी क्षमता वाला अत्याधुनिक ई-मेथनॉल प्लांट स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। दैनिक 150 टन स्वच्छ ग्रीन फ्यूल का उत्पादन समुद्री पोत परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने के साथ-साथ आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाने में भी सहायक होगा। ग्रीन विजन के साथ इस औद्योगिक इकाई के कार्यान्वित होने से पूरे गुजरात सहित कच्छ की औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 3500 से अधिक रोजगार के सुनहरे अवसर सृजित होंगे। जिससे स्थानीय युवाओं, इंजीनियरों, टेक्निकल वर्कफोर्स के अलावा लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन से जुड़े स्थानीय व्यापारियों और श्रमिकों के लिए आजीविका के उचित अवसर उपलब्ध होंगे। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के ग्रीन पोर्ट्स, सस्टेनेबल समुद्री परिवहन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री कांतिभाई अमृतिया, शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा, कच्छ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रभाबेन हुण, कच्छ-मोरबी के सांसद श्री विनोदभाई चावड़ा, अग्रणी श्री देवजीभाई वरचंद, महापौर श्रीमती दिव्याबेन नाथाणी, विधायक सर्वश्री अनिरुद्धभाई दवे, विरेन्द्रसिंह जाडेजा, श्रीमती मालतीबेन महेश्वरी, कच्छ जिला कलेक्टर श्री अनिलकुमार राणावसिया, गांधीधाम मनपा आयुक्त श्री बीडी डवेरा, जिला विकास अधिकारी श्री उत्सव गौतम, पूर्व कच्छ पुलिस अधीक्षक श्री सागर बागमार सहित कई पदाधिकारी, प्रशासन के उच्च अधिकारी, पोत परिवहन प्रशासन के अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

'सेवा संकल्प अभियान' के तहत गांधीधाम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का जनसंवाद : सेवा सेतु कार्यक्रम में लोगों के बीच मौजूद रहे मुख्यमंत्री

सरकार की योजनाओं को हाशिये पर खड़े लोगों तक पहुंचाना ही हमारा संकल्प : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शनिवार को कच्छ जिले के गांधीधाम में महानगर पालिका की ओर से आयोजित 12वें चरण के सेवा सेतु कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नागरिकों के साथ सीधे संवाद भी किया।

'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण करना है।

गांधीधाम में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का दौरा किया और लाभार्थियों से उन्हें मिल रहे योजनाओं के लाभों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, फ्री शिप कार्ड और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की सहायता के आदेश और मंजूरी पत्रों का वितरण भी किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने राम कृष्ण सेवा ट्रस्ट की ओर से दिव्यांगों को उपकरण सहायता वितरित की।

इस अवसर पर उपस्थित लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र के साथ काम कर रही है। सेवा सेतु जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार खुद लोगों के बीच जाकर उनके काम करती है। हमारा संकल्प है कि हाशिये पर खड़े लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी नागरिक सरकारी सेवा से वंचित न रहे। सेवा सेतु कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें एक ही स्थल पर लोगों को सभी प्रकार की सरकारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं।

सेवा सेतु कार्यक्रम में आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड में सुधार, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विधवा सहायता और वृद्ध सहायता सहित 56 से अधिक सेवाएं एक ही स्थल पर उपलब्ध कराई गईं। बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया और स्थल पर ही अपनी समस्याओं का निराकरण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

कार्यक्रम में श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री कांतिलाल अमृतिया, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री त्रिकमभाई छांगा, सांसद विनोदभाई चावड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष मती प्रभाबेन हुण, विधायक सर्व मती मालतीबेन महेश्वरी, अनिरुद्धभाई दवे, विरेन्द्रसिंह जाडेजा, गांधीधाम की महापौर मती दिव्याबेन नाथाणी, उप महापौर नवीनभाई जरू, कलेक्टर अनिल राणावसिया, गांधीधाम मनपा आयुक्त बीडी डावेरा, जिला विकास अधिकारी उत्सव गौतम, अग्रणी देवजीभाई वरचंद, धवलभाई आचार्य, सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

शिक्षा जगत के लिए एक कलंक: देश और गुजरात में छात्रों की आत्महत्याओं में वृद्धि हो रही है

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

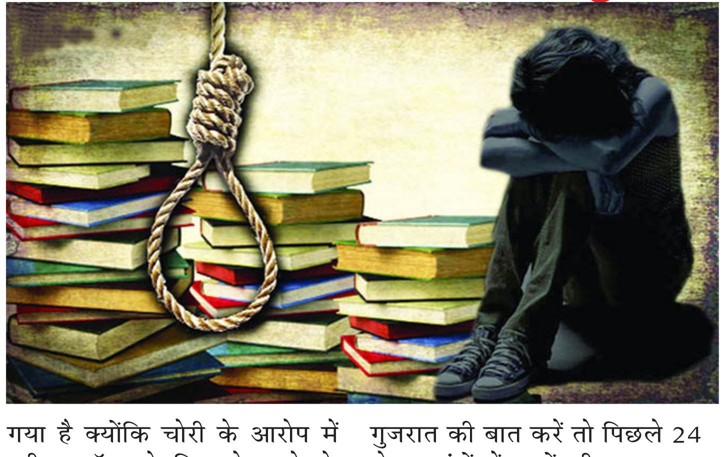

पिछले 48 घंटों में गुजरात में छात्रों की आत्महत्या की दो बेहद दुखद घटनाएं शिक्षा जगत के लिए कलंक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हाल ही में गुजरात समेत देश के शिक्षा जगत में शिक्षा के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया था। अब परीक्षा में चोरी करते पकड़े गए शिक्षक के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है।

इस प्रकार, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार स्वयं शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेती। प्रवेश से लेकर परीक्षाओं तक, शिक्षा क्षेत्र में चोरी और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई हैं। हाल ही में, यह पूरा मामला राजनीतिक उथल-पुथल में घिर गया है क्योंकि चोरी के आरोप में परीक्षा हॉल से निकाले जाने के बाद आईआईटी मुंबई के एक छात्र की आत्महत्या के पीछे का मुख्य कारण सामने आया है। जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा इकलौता बेटा आत्महत्या कर लेता है, तो उसके माता-पिता के लिए मानो आसमान ही गिर गया हो। मृतक साहिल के माता-पिता भूख हड़ताल पर बैठे हैं और संबंधित प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

गुजरात की बात करें तो पिछले 24 से 48 घंटों में छात्रों की आत्महत्या की दो बेहद दुखद घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें राजकोट और सूरत के दो छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। कल, 25 तारीख को, राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्र ने सुबह आत्महत्या कर ली। इसके अलावा, 5 दिन पहले (19 सितंबर को), आंध्र प्रदेश की एक 19 वर्षीय छात्रा ने भी इसी विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल की 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार, यह थोड़े ही समय में यहां दूसरी घटना है। इस प्रकार, मारवाड़ी विश्वविद्यालय में आत्महत्या करने वाले दोनों ही छात्र आंध्र प्रदेश के मेधावी छात्र थे। अब, 25 सितंबर को, सूरत के न्यू सिविल अस्पताल मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। इस छात्र की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई, उसने अपने हाथ की नसें काट ली थीं।

इस प्रकार, यदि हम पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नज़र डालें, तो आईआईटी में 53 भारतीय छात्रों की मृत्यु हुई है। इनमें से पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। यह न केवल शिक्षा जगत के लिए शर्मनाक है, बल्कि 'सबका साथ सबका विकास' सूत्र के लिए भी एक कलंक है।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह साबरमती में 1,542 करोड़ से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ

भारत की पहली LNG ट्रेन, कवच, स्वचालित सिग्नलिंग, WAG-12 लोको शेड और साबरमती-सरखेज दोहरीकरण से रेल सुरक्षा, क्षमता और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा नया आयाम

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 27 सितंबर 2026 को साबरमती में 1,542 करोड़ से अधिक की विभिन्न महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, माननीय सांसद श्री हसमुखभाई पटेल, माननीय सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा, माननीय महापौर श्री हितेशभाई बारोट, अहमदाबाद एवं गांधीनगर क्षेत्र के माननीय विधायकगण सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

इनमें WAG-12 साबरमती लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड का लोकार्पण, साबरमती–साणंद–भांडू मोटीदाऊ एवं साबरमती–कलोल–जखवाड़ा रेलखंड पर स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली का लोकार्पण, साबरमती–सरखेज रेल लाइन का दोहरीकरण, अहमदाबाद–पालनपुर एवं अहमदाबाद–सामाखियाली रेलखंड पर कवच प्रणाली का शिलान्यास तथा WAG-12 विद्युत इंजन एवं भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना शामिल है।

मानक कवच प्रणाली से रेल सुरक्षा को मिलेगी और अधिक मजबूती

अहमदाबाद मंडल में लगभग 411 करोड़ की लागत से कुल 404 किलोमीटर रेलखंड को स्वदेशी मानक कवच (Standard Kavach) प्रणाली से सुसज्जित किया जा रहा है। इसमें अहमदाबाद–पालनपुर सेक्शन के 157 किलोमीटर तथा अहमदाबाद–सामाखियाली सेक्शन के 247 किलोमीटर रेलखंड शामिल हैं।

अहमदाबाद–सामाखियाली मुख्य लाइन सेक्शन में कवच प्रणाली के कमीशनिंग के साथ ब्लॉक सेक्शनों में आधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। यह प्रणाली ट्रेनों के बीच सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने तथा मानवीय त्रुटियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कवच के प्रमुख लाभ

- आमने-सामने की टक्कर के जोखिम को कम करने में सहायता।
- पीछे से होने वाली टक्कर की संभावना को कम करना।
- निर्धारित गति सीमा से अधिक गति होने पर सुरक्षा प्रदान करना।
- ट्रेन परिचालन की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता में वृद्धि।
- आधुनिक स्वदेशी तकनीक के माध्यम से सुरक्षित रेल परिचालन को बढ़ावा।

▶▶ स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग से रेल परिचालन को मिलेगी नई गति

अहमदाबाद मंडल के साबरमती–कलोल–भांडू मोटीदाऊ तथा साबरमती–साणंद–जखवाड़ा सेक्शनों में कुल 122.57 किलोमीटर रेलखंड पर लगभग 118.83 करोड़ की लागत से स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग (ABS) प्रणाली का प्रावधान किया गया है।

यह आधुनिक प्रणाली ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने में सहायता करेगी तथा एक ही रेल मार्ग पर अधिक ट्रेनों का सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन संभव बनाएगी। इससे सेक्शन की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, परिचालन अधिक सुचारु होगा तथा ट्रेनों की समयपालन क्षमता में सुधार होगा।

मुख्य लाभः सुरक्षित दूरी अधिक लाइन क्षमता बेहतर समयपालन कम मानवीय हस्तक्षेप अधिक कुशल परिचालन

भारतीय रेल की पहली LNG ट्रेन: स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अभिनव पहल

भारतीय रेल ने स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल एवं किफायती रेल परिचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार ट्रेन की Driving Power Car (DPC) में LNG आधारित Fuel प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया है।

साबरमती स्थित इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो में 1400 HP क्षमता वाली 02 ट्रेनों की DPC को डीजल+LNG ड्यूल फ्यूल प्रणाली में परिवर्तित किया गया है। इसमें डीजल के स्थान पर लगभग 40 प्रतिशत तक LNG का उपयोग किया जा रहा है। दोनों DPC पर 2000 किलोमीटर से अधिक का सफल फील्ड ट्रायल पूरा किया जा चुका है।

LNG के उपयोग से ईंधन लागत में कमी के साथ-साथ CO, NOx एवं पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक उत्सर्जनों को कम करने में सहायता मिलेगी। परीक्षण आंकड़ों के अनुसार, एक DPC से लगभग 11.9 लाख प्रतिवर्ष तथा 8-कोच रेक से लगभग 23.9 लाख प्रतिवर्ष की बचत संभव है।

यह पहल ऊर्जा दक्षता, कम कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण-अनुकूल रेल परिवहन की दिशा में भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

साबरमती में 700 करोड़ का अत्याधुनिक WAG-12 अनुरक्षण शेड उच्च क्षमता वाली माल ढुलाई को मिलेगा नया आधार

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल स्थित साबरमती लोकोमोटिव शेड को 300 अत्याधुनिक WAG-12 HHP विद्युत लोकोमोटिव के होमिंग एवं अनुरक्षण हेतु लगभग 700 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। WAG-12 लोकोमोटिव लगभग 12,000 HP क्षमता वाले उच्च क्षमता के विद्युत लोकोमोटिव हैं, जो भारी एवं लंबी मालगाड़ियों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

300 WAG-12 लोकोमोटिव के अनुरक्षण के लिए M/s Madhepura Electric Locomotive Private Limited (MELPL) तथा लोकोमोटिव शेड, साबरमती के मध्य Maintenance Service Agreement (MSA) निष्पादित किया गया है। वर्तमान में 154 WAG-12 लोकोमोटिव होम किए जा चुके हैं तथा वर्ष 2027-28 तक कुल 300 लोकोमोटिव प्राप्त होने की योजना है।

प्रमुख लाभ

- WAG-12 लोकोमोटिव की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि।
- अत्याधुनिक सुविधाओं से अनुरक्षण दक्षता में सुधार।
- भारी एवं लंबी मालगाड़ियों के संचालन को बढ़ावा।
- माल ढुलाई क्षमता एवं परिचालन दक्षता में वृद्धि।
- वैज्ञानिक अनुरक्षण एवं बेहतर तकनीकी पर्यवेक्षण।
- भविष्य की अनुरक्षण आवश्यकताओं के लिए मजबूत एवं आधुनिक अवसंरचना।

▶▶ साबरमती–सरखेज रेलखंड दोहरीकरण परियोजना; रेल क्षमता और सरखेज–धोलेरा कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम

लगभग 313.27 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर लंबे साबरमती–सरखेज रेलखंड के दोहरीकरण की परियोजना अहमदाबाद क्षेत्र में बढ़ती रेल यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस परियोजना के अंतर्गत साबरमती, गांधीग्राम, वस्त्रापुर एवं सरखेज स्टेशन शामिल हैं। परियोजना में 16 लघुपुल, 13 रोड अंडर ब्रिज (RUB), 1 मेजर पुल तथा 6 समपार फाटकों से संबंधित कार्य शामिल हैं।

परियोजना के प्रमुख लाभ

- रेल लाइन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि।
- अधिक ट्रेनों के सुचारु एवं निर्बाध संचालन में सुविधा।
- ट्रेनों के डिटेंशन एवं परिचालन बाधाओं में कमी।
- यात्री एवं माल यातायात के लिए बेहतर रेल संपर्क।
- सरखेज–धोलेरा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूती।
- औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा।
- क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसरों को गति।